

“आज के मुख्य समाचार”

- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा—राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा गंभीर असर।
- केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कर्ज के बोझ से बचने के लिए राज्यों को वित्तीय अनुशासन अपनाने की दी सलाह।
- भाजपा का आरोप—झूठे वायदों और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पूरी तरह विफल रही प्रदेश सरकार।
- प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा—अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम—2025 कल से होगा लागू—सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना रहेगा उद्देश्य।

आरडीजी

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। शिमला में आज मंत्रिमंडल की बैठक और वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार हैं।

केन्द्र सरकार के बजट में प्रदेश का राजस्व घाटा अनुदान यानि आर.डी.जी. बंद किए जाने को लेकर गतिरोध जारी है। इस अनुदान की समाप्ति के प्रभावों और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर वित्त विभाग द्वारा आज शिमला में प्रस्तुति दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त करना सरकार का नहीं, बल्कि राज्य की जनता के अधिकारों का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यदि एक बार आरडीजी का प्रावधान समाप्त किया जाता है, तो राज्य की जनता के अधिकारों को सुरक्षित रख पाना कठिन हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार अदालत का रुख करेगी। उन्होंने विपक्ष को भी इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष हिमाचल के हितों की पैरवी करने की सलाह दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त विभाग की प्रस्तुति के दौरान विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनका इसमें शामिल न होना प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

केन्द्रीय मंत्री

दूसरी ओर, राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में विभिन्न राज्यों द्वारा वित्तीय अनुशासन न अपनाने से राज्यों पर कर्ज का

बोझ बढ़ रहा है। शिमला में आज संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि फिसकल डेफिसिट कम करने पर केन्द्र सरकार का फोकस है।

डिस्पैच : शिमला में केन्द्रीय बजट पर आधारित संवाददाता सम्मेलन में केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि राज्यों की खराब आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन न होने के चलते 12वें वित्त आयोग की ओर से दी गई आर.डी.जी. अगले वित्त आयोगों की ओर से भी अस्थायी रूप से जारी रखी गई। उन्होंने कहा कि कर्ज के बोझ से बचने के लिए सभी राज्यों को वित्तीय अनुशासन अपनाने की ज़रूरत है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सशक्त व विकसित बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बजट सभी वर्गों के सतत विकास का बजट है जिसमें नागरिकों के क्षमता विकास को केंद्र सरकार ने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य और सतत विकास का बजट पेश किया है जिसमें देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है।

इस बीच केंद्रीय मंत्री ने शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रबुद्धजन संगोष्ठी में भी शिरकत की। केन्द्रीय बजट को लेकर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट रोजगार सृजन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर सबसे अधिक केंद्रित है।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार झूठे वायदों और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पूरी तरह विफल साबित हुई है। धर्मशाला में आज प्रत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी गारंटियां पूरा करने के बजाए सरकार अब जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। बिंदल ने ये भी आरोप लगाया कि 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश में विकास कार्य ठप्प हैं।

जयराम ठाकुर

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर धकेला है। कांगड़ा ज़िले के नगरोंटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सब कुछ बंद करने और बदलने की जिद ने आज प्रदेश को दयनीय मोड़ पर खड़ा कर दिया है। जयराम ठाकुर ने स्थानीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सरकार की जनविरोधी नीतियों को बेनकाब करने का आह्वान किया। इस बीच देहरा में भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के अभ्यास वर्ग में जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां कर्मचारी और प्रदेश विरोधी रही हैं।

सिकंदर कुमार

राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को विकसित भारत 2047 के विराट दृष्टिकोण का जीता जागता प्रमाण बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केंद्रीय बजट के सार्थक और दूरगामी परिणाम सामने आएंगे जिससे आम लोगों का जीवन और बेहतर होगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि इस बजट के माध्यम से भारत अपने विकसित और आत्मनिर्भर के संकल्प को पूरा करने में निश्चित रूप से सफल होगा।

अधिनियम

प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा—अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम—2025 कल से लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना है। इस कानून के अंतर्गत, अब नकल, प्रश्न पत्र लीक, जालसाजी और परीक्षा संबंधी संगठित अपराधों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम के अनुसार, भर्ती परीक्षाओं में नकल करने या नकल में सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष के कारावास के साथ एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के अनुसार परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और उनके कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की गई है।

अनुराग ठाकुर

सांसद अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा ज़िले के देहरा में आज निर्माणाधीन केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विश्वविद्यालय के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों को उत्तम शैक्षणिक अनुभव व विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश को वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। चंडीगढ़ में कल शाम एक समारोह में उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के विकास सहित नई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार सभी वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

स्मार्ट मीटर

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा इन दिनों पुराने बिजली मीटरों को नए स्मार्ट मीटर में बदला जा रहा है। बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कल 9 फरवरी से 23 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के पहले दिन कल शिमला में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर”

- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुखबू ने कहा—राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा गंभीर असर।
- केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कर्ज के बोझ से बचने के लिए राज्यों को वित्तीय अनुशासन अपनाने की दी सलाह।
- भाजपा का आरोप—झूठे वायदों और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पूरी तरह विफल रही प्रदेश सरकार।
- प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा—अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम—2025 कल से होगा लागू—सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना रहेगा उद्देश्य।

=====